CENTRE FOR SCIENCE AND ENVIRONMENT

MAIN OFFICE: 41, Tughlakabad Institutional Area, New Delhi-110 062 INDIA
Tel: +91 (011) 4061 6000, 2995 5124, 2995 6110 **Fax:** +91 (011) 2995 5879 **Email:** cse@cseindia.org **Website:** www.cseindia.org
BRANCH OFFICE: Core 6A, Fourth Floor, India Habitat Centre, Lodhi Road, New Delhi-110 003
Tel: +91 (011) 2464 5334, 2464 5335

LEAVES
OF
IMPORTANT
SURVIVAL
TREES
IN
INDIA —
MAHUA,
KHEJDI,
ALDER,
PALMYRA
AND
OAK

सीएसई प्रेस विज्ञप्ति

कैपिटान अमेरिका और उसके जलवायु संबंधी वायदेः बिना किसी बात हो–हल्ला

नई दिल्ली–स्थित, सेंटर फॉर सांइस एंड एन्वायरमेंट (सीएसई) ने अमेरिका की जलवायु कार्य–योजना का विस्तृत अध्ययन जारी किया और उसका यह कहना है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बहुत काम कर रही हैं।

- सीएसई अमेरिकी आईएनडीसी को ''गैर–महात्वाकांक्षी और अन्यायपूर्ण कहता है।
- एक दक्षिणी थिंक टैंक से अपनी तरह के पहले अध्ययन में, सीएसई ने कहा कि यह महज आम कार्रवाई है।
- अध्ययन में यह पाया गया कि अमेरिका में ऊर्जा प्रणाली जीवाश्म ईंधन आधारित ही बनी रहेगी जिसमें से कुल प्रमुख ऊर्जा का 76 फीसदी 2030 में जीवाश्म ईंधनों से मिल रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान 2030 तक महज 15 फीसदी होगा।
- अमेरिका ने अपने गतिशीलता पैटर्न में बदलाव करने के लिए कोई ख़ास देशव्यापी नीति नहीं बनाई है। 86 प्रतिशत लोग वाहन चलाते हैं और सार्वजनिक परिवहन में की गई यात्राओं में कमी आ रही है, न कि बढ़ोत्तरी हो रही है।
- अमेरिका में भवनों के लिए ऊर्जा दक्षता मानदंड स्वैच्छिक और कमजोर हैं। इसके अलावा, अमेरिकी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े घर बना रहे हैं और अधिक उपकरण खरीद रहे हैं जिससे दक्षता में सुधार में कोई फायदा नहीं हो रहा है।
- उद्योग क्षेत्र ही एममात्र ऐसा क्षेत्र हैं जहां ऊर्जा और उत्सर्जन में कमी आई है। लेकिन ऐसा अमेरिका के उत्सर्जन को आउटसोर्स करने की वजह से है। अमेरिका में खपत माल का 60 प्रतिशत आयात किया जा रहा है।
- कुल मिलाकर, जीएचजी उत्सर्जन में नीति द्वारा प्रेरित गिरावट का कोई प्रमाण नहीं है। यह उत्सर्जन के रुझानों से स्पष्ट हैं जो वर्ष 2007–08 में गिरावट (मंदी की वजह से) के बाद फिर से उछाल है।
- अमेरिका द्वारा हमेशा की तरह व्यवसाय के दृष्टिकोण का अर्थ है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने का बोझ अब भारत जैसे अन्य देशों को उठाना होगा। यह दुनिया को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की खतरनाक जोखिम में भी डाल रहा है– जिसे भारत जैसे देशों में स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है जहां अनियमित मौसम अब नए तौर पर 'सामान्य' बनता जा रहा है और यह सबसे गरीब और सबसे कमजोर को भारी नुकसान हो रहा है।
- यह कड़वा सच है। सबसे अधिक कचोटने वाला। अमेरिका की खपत और जीवनशैली में परिवर्तन करना होगा।

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2015: अमेरिकन इंटेंडेड नेशनल डिटर्माइन्ड कंट्रीब्यूशन (आईएनडीसी) के गंभीर अभियोग में, दिल्ली–आधारित सेंटर फॉर सांइस एंड एन्वायरमेंट (सीएसई) ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के लिए अमेरिका कुछ भी अतिरिक्त नहीं कर रहा है; अधिकांश परिवर्तन, आर्थिक कारणों से एवं बाजार की ताकतों के कारण नैसर्गिक तौर पर और स्वतः घटित हो रहे हैं। इससे भी बदतर है, अधिक वृद्धि और खपत की वजह से इन सुधारों को गंवाया जा रहा है। केंद्र ने आज यहाँ अपना अध्ययन जारी किया –जिसका शीर्षक ''कैपिटान अमेरिकाः यूएस क्लाइमेट गोल्स–रिकॉनिन्ग'' है।

सीएसई की महानिदेशक सुनीता नारायण ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा ''यूएस आईएनडीसी न तो महत्वाकांक्षी है और न ही न्यायसंगत है''। सीएसई पहला दक्षिणी थिंक टैंक है जिसने अमेरिका के जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों के बारे में विस्तृत विश्लेषण किया है।

नारायण ने यह भी कहा, ''हमारा विश्लेषण दर्शाता है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के प्रमुख आर्थिक क्षेत्र– ऊर्जा, परिवहन, उद्योग आदि – चालू हैं और 2030 तक ऐसे ही चलते रहेंगे चाहे बाकी दुनिया जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए कटिबद्ध तत्पर हो जाए''।

Founder Director
ANIL AGARWAL

EXECUTIVE BOARD

Chairperson
M.S. SWAMINATHAN

Director General
SUNITA NARAIN

Deputy Director General
CHANDRA BHUSHAN

Members
B.D. DIKSHIT
BHARATI CHATURVEDI
G.N. GUPTA
JAGDEEP GUPTA
MAHESH KRISHNAMURTHY
N.C. SAXENA
N.J. Rao
WILLIAM BISSELL

ऊर्जा के बारे में

सीएसई के उप महानिदेशक, चंद्र भूषण ने कहाः ''अमेरिका ने कार्बन के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करने के बाबत नीतियां लागू नहीं की हैं। इसका परिणाम यह है कि अमेरिका आज की तुलना में 2030 में 20 फीसदी अधिक जीवाश्म ईंधनों का उत्पादन और उपभोग करेगा। 2030 में प्रमुख ऊर्जा का लगभग 15 फीसदी योगदान अक्षय ऊर्जा से आएगा जो वर्तमान 11 फीसदी से अधिक है।

भूषण ने कहाः ''स्वच्छ ऊर्जा योजना (सीपीपी), बिजली के क्षेत्र से उत्सर्जन को कम करने के लिए राष्ट्रपति ओबामा की सर्वाधिक महत्वाकांक्षी जलवायु परिवर्तन कार्य योजना भी आम कार्रवाई से कम महत्वाकांक्षी है। 2005–2014 में, बिजली क्षेत्र के उत्सर्जन में सालाना 1.8 प्रतिशत की कमी आई है, काफी हद तक कोयले को छोड़कर प्राकृतिक गैस को अपनाने की वजह से। स्वच्छ ऊर्जा योजना के अंतर्गत, अब से लेकर 2030 तक इससे महज 1.6 फीसदी की कमी आएगी। 2030 में भी, अमेरिकी की बिजली के लगभग 60 फीसदी का उत्पादन कोयले और गैस से किया जाएगा।''

परिवहन के बारे में

जबकि बाकी दुनिया को यह एहसास है कि परिवहन संबंधी उत्सर्जन पर लगाम कसने के लिए गतिशीलता को पुनः अविष्कार करने की अपेक्षा है ताकि लोग आगे बढ़े, कारें नहीं, अमेरिका रिवर्स गियर में हैं। सार्वजनिक परिवहन से प्रति व्यक्ति यात्राओं में गिरावट आई है और अमेरिका रूका हुआ है; 86 प्रतिशत अमेरिकी कारों से आते–जाते हैं– यह एक ऐसा रूझान है जिससे बदलाव का कोई संकेत नहीं मिलता। यात्री कार उत्सर्जन में सालाना 1 फीसदी की वृद्धि हो रही है, और अनुमान है कि 2017 में कारों की सर्वाधिक बिक्री होगी।

नारायण ने कहा, ''हमारे विश्लेषण दर्शाते हैं कि वाहनों के लिए ईंधन दक्षता मानकों पर अमेरिका पर अधिक निर्भरता पर्याप्त नहीं है। चूंकि वाहन और अधिक कुशल होते जा रहे हैं, अमेरिकी गाड़ी अधिक चला रहे हैं। अमेरिका को निजी कारों से दूरी बनानी होगी।''

भवनों के बारे में

1980–2009 में, अमेरिका के घरेलू क्षेत्र में ऊर्जा की तीव्रता में 37 प्रतिशत की जबरदस्त गिरावट आई। लेकिन इसी अवधि में, अधिक घरों का निर्माण किया गया और घरों के आकार में 20 फीसदी की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान, 'कुशल' उपकरणों के उपयोग में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई – इन सभी का तात्पर्य हुआ कि वास्तविक ऊर्जा उपभोग जस का तस बना रहा और इसमें गिरावट नहीं आई। इस प्रकार जो भारी फायदा मिल सकता था, गवां दिया गया।

उद्योग के बारे में

अमेरिका में केवल उद्योग ही ऐसा क्षेत्र है जिसमें उत्सर्जन और ऊर्जा की खपत में कमी आई है। लेकिन औद्योगिक माल की खपत आ. समान छू रही है। इन वस्तुओं का विनिर्माण अमेरिका नहीं कर रहा है। इसके बजाय, अब खरीदी गई सभी वस्तुओं का 60 प्रतिशत आयातित वस्तुएं हैं। नारायण कहती हैंः ''इसका आश्य है कि औद्योगिक उत्सर्जन कम नहीं हुआ है, वरन महज इसे आउटसोर्स किया गया है।''

उपभोग समस्या है

अमेरिका की जलवायु नीति में वस्तुओं और सेवाओं की तेजी से बढ़ती खपत के मुद्दे का समाधान नहीं किया गया है। अमेरिका में उपभोग व्यय मूल्य में 1990 के बाद से नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। मूल्य के संदर्भ में, अमेरिका में 1990–2014 के दौरान वस्तुओं और सेवाओं का कुल उपभोग दोगुना हो गया है।

भूषण ने कहाः ''अमेरिका में प्रति व्यक्ति गृहस्थ उपभोग, यूरोपीय संघ– 28 के गृहस्थ उपभोग के मुकाबले दोगुना, चीनी गृहस्थ उपभोग के मुकाबले 24 गुना, भारतीय गृहस्थ उपभोग के मुकाबले 44 गुना, बांग्लादेश में गृहस्थ उपभोग के मुकाबले 64 गुना और मालावी गृहस्थ के मुकाबले 173 गुना अधिक है। अमेरिका, खपत के इस उच्च स्तर को कम किए बिना, जलवायु परिवर्तन का वास्तव में समाधान नहीं कर सकता।''

सस्ती ऊर्जा से उपभोग को बढ़ावा मिलता है

ऊर्जा की खपत और इस कारण, कार्बन डाई–ऑक्साइड के उत्सर्जन में वृद्धि का ऊर्जा की सस्ती कीमत से सीधा संबंध है। अमेरिका में, ऊर्जा की कीमतें कम बनी रहीं हैं और इनमें और अधिक कमी हो रही है। अमेरिका में 1990–2014 में, शहरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 81 फीसदी बढ़ा, लेकिन रिहायशी बिजली की प्रति इकाई लागत में 12 फीसदी तक कमी की गई। परिणामः प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 1990 में 11,373 किलो वाट घंटे/सालाना (किलोवाट घंटा/वर्ष) से बढ़कर 2014 में 11,373 किलो वाट घंटे/सालाना हो गई। भूषण ने कहा, ''मूल्यों में ये गिरावटें वास्तव में ऊर्जा दक्षता में सुधार करने के लिए किए गए सभी प्रयासों के लिए विरोधी थीं।''

सीएसई के प्रमुख निष्कर्ष

- अमेरिका की आईएनडीसी न तो महत्वाकांक्षी है और न ही न्यायसंगतः अमेरिका की यूएनडीसी में उत्सर्जन में 2025 तक 26–28 प्रतिशत तक कम करना है जो 2005 के स्तर से नीचे हैं। यह 2025 तक उत्सर्जन में महज 13–15 फीसदी तक की कटौती के बराबर है जो 1990 के स्तरों से नीचे हैं। इसका अर्थ है कि 2025 में, प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 13.5 टन होने हो जाएगा। इसकी तुलना में, यूरोपीय संघ 2030 तक 1990 के स्तरों से 40 प्रतिशत की कमी लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका मतलब हुआ कि 2025 में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 7.0 टन– अमेरिकी उत्सर्जन का लगभग आधा हो जाएगा। 2025 में भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 3.0–3.5 टन– अमेरिकी प्रति व्यक्ति उत्सर्जन का एक–चौथाई होगा।
- अमेरिका का बाकी कार्बन में गैर आनुपातिक तौर पर अधिक हिस्सा बना रहेगा जैसा इसने विगत में किया है। अमेरिका, जिसकी आबादी विश्व की जनसंख्या का 5 फीसदी हैं, 2030 तक विश्व बजट के 17.25 प्रतिशत का उपभोग करेगा। 2030 के बाद, अन्य देशों के लिए बमुश्किल कोई कार्बन बजट शेष होगा।
- 2005 के बाद अमेरिका के जीएचजी उत्सर्जन में नीति–प्रेरित गिरावट का कोई प्रमाण नहीं है। वास्तव में, अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ रही है, साथ ही उपभोग और उसके परिणामस्वरूप, उत्सर्जन में भी उछाल है।
- सभी अमेरिकी जलवायु परिवर्तन कार्य योजनाएं, घरेलू के साथ–साथ आईएनडीसी आम हैं। इनसे अर्थव्यवस्था निम्न कार्बन उत्सर्जक नहीं बन रही है।
- अमेरिका, महत्वाकांक्षी कार्रवाई न करके, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने का बोझ अन्य देशों पर डाल रहा है।
- एक विभाजनकारी शक्ति, जबकि हम पेरिस के लिए तैयार हैं
- अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में सबसे बड़ी विभाजनकारी शक्ति रहा है। अमेरिका की कोई घरेलू–कार्रवाई न करने की एप्रोच से संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन एक ऐसे मंच से बदलकर, जहां प्रत्येक राष्ट्र से ''साझा किंतु भिन्न उत्तरदायित्व एवं संबंधित क्षमताओं'' पर आधारित कार्रवाई करने की उम्मीद थी, ऐसा मंच बन गया है जहां विभिन्न देश एक–दूसरे से पीछे रहने की होड़ में हैं।
- नारायण का कहना हैं, ''अमेरिका की हल्की महत्वाकांक्षा का मतलब है कि प्रत्येक की महत्वाकांक्षाएं निम्न हैं। आज की जलवायु परिवर्तन कार्य योजना की शब्दावली में ''बॉटम–अप'', ''राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित कार्रवाई'' और ''स्वैच्छिक'' को अपनाया हुआ है। ये अमेरिका के आविष्कार और उसके गढ़े हुए हैं। केवल अमेरिका के लिए उपयुक्त है।''
- उन्होंने यह भी पूछाः ''दुनिया के सामने पेश आ रहा बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका की सुविधा के लिए जलवायु करार फिर से किया जाए– जैसा 2010 में कैनकन में और 2011 में डरबन में किया गया था? या, एक ऐसा वैश्विक समझौता तैयार करने के लिए दुनिया को एकजुट होना चाहिए, जो गरीब और सर्वाधिक प्रभावित के अनुरूप हो? पेरिस में यही मुद्दा है। और अधिक कुछ नहीं। बाकी सब देखने–दिखाने के लिए है।''